भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3064
जिसका उत्तर बृहस्पतिवार 22 मार्च, 2018 को दिया जाना है

इलेक्ट्रिक वाहनों की उच्च लागत

3064. श्री परिमल नथवानी:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशुद्ध इलेक्ट्रिक वाहनों की उच्च लागत उसके लोकप्रिय होने में बाधक है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए औपचारिक रूप से फेम (एफएएमई) इंडिया योजना प्रारंभ की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या मंत्रलय ने अनुसंधान तथा विकास, खासकर ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए, 200 प्रतिशत प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया है; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख): नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020 (एनईएमएमपी-2020) ने संभावित वाधा कारकों में से एक के रूप में विशुद्ध इलेक्ट्रिक वाहनों की उच्च लागत को चिन्हित किया। तदनुसार, स्कीम की राजपत्र अधिसूचना, दिनांक 13 मार्च, 2015 [एस.ओ.सं. 830(ई)] के अनुबंध 13 के अनुसार और जैसा कि समय-समय पर संशोधन किया गया, फेम इंडिया स्कीम में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के लिए मांग प्रोत्साहन शामिल किए गए, जो भारी उद्योग विभाग की वेबसाइट (www.dhi.nic.in) पर उपलब्ध है।

(ग): जी नहीं।

******